International Journal Of Multidisciplinary Research In Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 3, Issue 12, December 2020 |

कोविड-19 एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

डॉ. भानु प्रताप सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, डी० ए० वी० कॉलेज, कानपुर

सार

भारत में कोविड-19 कोरोनावायरस महामारी का आर्थिक प्रभाव काफी हद तक विघटनकारी रहा है। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार भारत की वृद्धि दर घटकर 3.1% रह गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था -4.5 की दर से सिकुड़ जायेगी। विश्व बैंक और रेटिंग एजेंसियों ने शुरू में भारत के विकास का पूर्वानुमान किया जो कि भारत के 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद के तीन दशकों में सबसे कम आंकड़ों के साथ देखा गया अनुमान था। रिपोर्ट में वर्णित है कि यह महामारी ऐसे वक्त में आई है जबकि वित्तीय क्षेत्र पर दबाव के कारण पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती की मार झेल रही थी। कोरोना वायरस के कारण इस पर और दवाब बढ़ा गया है। हालाँकि, मई के मध्य में आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों को नकारात्मक आंकड़ों से और भी अधिक घटा दिया गया था। यह एक गहरी मंदी का संकेत था। क्रिसिल ने घोषणा की कि यह स्वतंत्रता के बाद से भारत की सबसे खराब मंदी होगी।भारत सरकार ने केरल में कोरोनावायरस के पहले मामले की पुष्टि की जब वुहान के एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा छात्र भारत लौटा था। भारत में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या 500 तक थी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी नागरिकों को 'जनता कर्फ्यू' करने को कहा था।

डिफॉल्टरों की संख्या में बढ़ोतरी
भारत की सबसे बड़ी स्वर्ण-वित्तपोषित कंपनियों में से एक, मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड (MNFL.NS) ने जनवरी-मार्च तिमाही में लगभग 55 मिलियन डॉलर मूल्य के सोने की नीलामी की, जबकि पिछली तीन तिमाहियों में यह 1.1 मिलियन डॉलर थी। विशेषज्ञों का कहना है कि सोने के आभूषणों को गिरवी रख कर सुरक्षित कर्ज लेने वाले लोगों में डिफॉल्टरों की संख्या बढ़ने से सोने की निलामी बढ़ रही है, जबकि सोने को गिरवी रखकर लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए आमतौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक की व्यवस्था है, ऐसे में सोने की निलामी दीर्घकालिक आर्थिक तनाव का संकेत है।

देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक ने आने वाले महीनों में खुदरा क्षेत्र में और अधिक गड़बड़ी की चेतावनी दी है, जिसमें व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यक्तियों को दिए गए ऋण शामिल हैं।वित्तीय क्षेत्र में अनिश्चितता के स्तर पर प्रकाश डालते हुए, एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन ने एक निवेशक कॉल पर कहा कि 'इतने सालों में पहली बार हमें इस बात की जानकारी नहीं हो रही है कि यह क्या हो रहा है।'भारत में चुनाव का सर्वे करने वाली एजेंसी 'सीवोटर' द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, बड़ी संख्या में लोगों के जीवन स्तर में तेजी से गिरावट आई है और अधिकांश लोगों को 'आने वाले 12 महीनों में आशा की कोई किरण नहीं दिख रही है।'

परिचय

कोरोनावायरस के कारण पूरे देश में लाकडाउन होने के कारण कई सरकारी व्यवसाय और उद्योग प्रभावित हुए हैं। घरेलू आपूर्ति और मांग प्रभावित होने के चलते आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित हुई है। वहीं जोखिम बढ़ने से घरेलू निवेश में सुधार में भी देरी होने की संभावना दिख रही है। विश्व बैंक के अनुसार इस महामारी की वजह से भारत ही नहीं बल्कि समूचा दक्षिण एशिया गरीबी उन्मूलन से मिलें फायदे को गँवा सकता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ ने कहा है कि कोरोना वायरस सिर्फ़ एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट नहीं रहा, बल्कि ये एक बड़ा लेबर मार्केट और आर्थिक संकट भी बन गया है जो लोगों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा। लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर अनौपचारिक क्षेत्र पर पड़ा है और हमारी अर्थव्यवस्था का 50 प्रतिशत जीडीपी अनौपचारिक क्षेत्र से ही आता है, ऐसे में ये क्षेत्र लॉकडाउन के दौरान काम नहीं कर पा रहे, वो कच्चा माल नहीं ख़रीद पा रहे और बनाया हुआ माल बाज़ार में नहीं बेच पा रहे जिससे उनकी कमाई बंद सी पड़ गई। कोरोनावायरस दुनिया में कहीं और की तुलना में भारत में तेजी से फैल रहा है, भारत में वर्तमान में 36 लाख से अधिक मामले हैं, और 65 हजार से अधिक मौतें हुई हैं। इस कारण भारत में मज़दूरों की कमी को कारण रोजगार को बड़ा नुकसान हुआ है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सार्वजनिक वित्त को लेकर खींचतान के बीच कोरोनावायरस मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है और मुद्रास्फीति बढ़ने का मतलब है कि सुधार जल्दी नहीं हो सकती है। कुछ का कहना है कि अर्थव्यवस्था में लगभग 10 प्रतिशत का संकुचन देखा जा सकता है।लाकडाउन के शुरू के दिनो

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 3, Issue 12, December 2020 |

में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश में 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को साकार करने के लिए घरेलू उद्योग को अधिक आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया था।[1,2]

लॉकडाउन के दौरान अनुमानित 14 करोड़ लोगों ने रोजगार खो दिया जबकि कई अन्य लोगों के लिए वेतन में कटौती की गई थी। देश भर में 45% से अधिक परिवारों ने पिछले वर्ष की तुलना में आय में गिरावट दर्ज की है। पहले 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को हर दिन 32,000 करोड़ से अधिक की हानि होने की आशंका थी। पूर्ण लॉकडाउन के तहत भारत के $2.8 ट्रिलियन आर्थिक संरचना का एक चौथाई से भी कम गतिविधि कार्यात्मक थी। अनौपचारिक क्षेत्रों में कर्मचारी और दिहाड़ी मजदूर सबसे अधिक जोखिम वाले लोग हैं। देश भर में बड़ी संख्या में किसान जो विनाशशील फल-सब्जी उगाते हैं, उन्हें भी अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। महामारी से ठीक पहले, सरकार ने कम विकास दर और कम मांग के बावजूद अर्थव्यवस्था को अनुमानित $2.8 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन तक बदलने का लक्ष्य रखा था।

इस वायरस से हवाई यात्रा, शेयर बाज़ार, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं सहित लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं।यह वायरस अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, जबकि इसके कारण चीनी अर्थव्यवस्था पहले से ही मुश्किल स्थिति में है। इन दो अर्थव्यवस्थाओं, जिन्हें वैश्विक आर्थिक इंजन के रूप में जाना जाता है, संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती तथा आगे जाकर मंदी का कारण बन सकता है।

भारत-चीन व्यापार संबंध:

भारत अपने कुल आयातित माल का 18%, इलेक्ट्रॉनिक घटक का 67% एवं उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का 45% चीन से आयात करता हैं।भारत जब अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे समय में इस वायरस का केवल सतही प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा ऐसे कठिन समय में समस्या का समाधान मात्र 'एयर लिफ्टिंग से संभव नहीं है।[3,4]

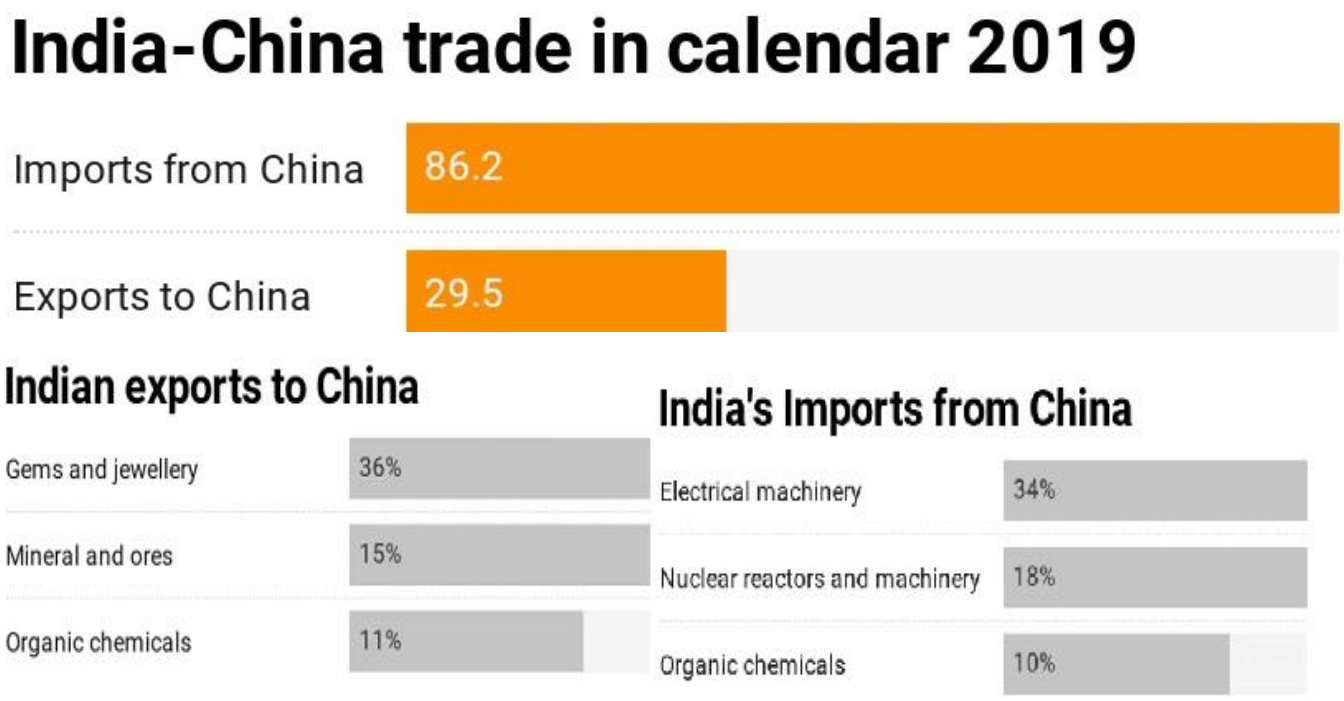

भारत जब अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे समय में इस वायरस का केवल सतही प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा ऐसे कठिन समय में समस्या का समाधान मात्र 'एयर लिफ्टिंग' से संभव नहीं है।यह समस्या न केवल आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करेगी, अपितु यह भारत के फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी।निर्यात, जिसे अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन माना जाता है, इसमें वैश्विक मंदी की स्थिति में और गिरावट देखी जा सकती है, साथ ही निवेश में भी गिरावट आ सकती है।

भारतीय कंपनियाँ चीन आधारित 'वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला' में शामिल प्रमुख भागीदार नहीं हैं, अत: भारतीय कंपनियाँ इससे अधिक प्रभावित नहीं होंगी।दूसरा, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है, जो कि वृहद् अर्थव्यवस्था और उच्च मुद्रास्फीति के चलते अच्छी खबर है।[5,6]

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 3, Issue 12, December 2020 |

वायरस जनित यह संकट किसी अन्य वित्तीय संकट से बिलकुल अलग है। अन्य वित्तीय संकटों का समाधान समय-परीक्षणित उपायों (Time-tested Measures) जैसे- दर में कटौती, बेल-आउट पैकेज (विशेष वित्तीय प्रोत्साहन) आदि से किया जा सकता है, परंतु वायरस जनित संकट का समाधान इन वित्तीय उपायों द्वारा किया जाना संभव नहीं है।

विचार-विमर्श

भारत सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए कई उपायों की घोषणा की जिनमें खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और राज्यों के लिए अतिरिक्त धन और कर चुकाने की समय सीमा बढ़ाना। गरीबों के लिए कई तरह के आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की गई जो कुल 1,70,000 करोड़ से अधिक थे।अगले दिन भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कई उपायों की घोषणा की जो देश की वित्तीय प्रणाली को 3,74,000 करोड़ उपलब्ध कराएंगे। साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए मार्च के बाद से प्रमुख ब्याज दरों में 115 आधार अंकों (1.15 प्रतिशत अंक) की कमी की है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए भारत को समर्थन को मंजूरी दी।

प्रधान मंत्री ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा की। इसमें समग्र आर्थिक पैकेज के रूप में 20 लाख करोड़ का पॅकेज घोषित किया गया। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 10% है। हालांकि यह प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया गया था लेकिन इसमें आरबीआई की घोषणाओं सहित पिछले सरकारी राहत पॅकेज को शामिल किया गया था। बेरोजगारी दर 6.7% थी जो बढ़कर 26% हो गई। फिर पूर्व-लॉकडाउन स्तर पर वापस आ गई। नरेंद्र मोदी द्वारा मई में घोषित जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर एक प्रोत्साहन पैकेज, जिसमें बैंक ऋण पर क्रेडिट गारंटी और गरीबों को मुफ्त अनाज शामिल हैं। इस पर कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि उस समर्थन का अधिकांश हिस्सा पहले से ही सरकार द्वारा बजट में लिया गया था और इसमें बहुत कम खर्च शामिल था।[7,8]

भारत सरकार को लगातार विकास की गति का अवलोकन करने की आवश्यकता है, साथ ही चीन पर निर्भर भारतीय उद्योगों को आवश्यक समर्थन एवं सहायता प्रदान करनी चाहिये। कोरोना वायरस जैसी बीमारी की पहचान, प्रभाव, प्रसार एवं रोकथाम पर चर्चा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा की जानी चाहिये ताकि इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके।

परिणाम

कोविड-19 महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अत्यधिक प्रभावित किया है। कोविड-19 के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया, जिससे लोगों का रोजगार एवं व्यवसाय प्रभावित हुआ। विश्व बैंक द्वारा जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) –3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस महामारी ने निम्नलिखित क्षेत्रें को प्रभावित किया है-

मांग में गिरावटः कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं (चावल, दाल आदि) की जमाखोरी देखी गई। परंतु लॉकडाउन के कुछ ही दिन बाद सब्जियों तथा फलों की मांग में लगभग 60 प्रतिशत तक की कमी हुई, क्योंकि थोक खरीदारों और रेस्तरां बंद होने के कारण इनकी खरीद नहीं की गई। आवश्यक वस्तुओं तथा सब्जियों और फलों के मूल्य में गिरावट के बाद विद्युत, डीजल तथा पेट्रोल की मांग में क्रमशः 9.2 प्रतिशत 26 प्रतिशत तथा 17 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, परंतु जून के शुरूआत से ही डीजल तथा पेट्रोल की दामों में बढोतरी हो रही है।

आवश्यक वस्तुओं तथा ईंधन की मांग में गिरावट के साथ ही साथ गैर-आवश्यक वस्तुओं (इलेक्ट्रोनिक, आभूषण आदि) जैसे क्षेत्रें में मांग में आकस्मिक गिरावट दर्ज की गई है। एक्सिस कैपिटल के एक अध्ययन के अनुसार भारत में विवेकाधीन खर्च में प्रति माह लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपये की कमी हो सकती है।[9,10]

आपूर्ति का बाधित होनाः कोविड-19 महामारी से हुए लॉकडाउन ने बड़ी कंपनियों की आपूर्ति शृंखलाओं को प्रभावित किया है और केवल अति आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन एवं वितरण तक सीमित कर दिया। देश के विभिन्न मंडियों में किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों के न होने या न्यूनतम गतिविधियों के संचालित होने, श्रम में कमी, परिवहन संबंधी समस्याओं और किसानों की अनिच्छा आदि के कारण कृषि उपज की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे थोक कीमतें कम हो गई।

कीमत में गिरावटः मांग और आपूर्ति के साथ-साथ बाजार की परिस्थितियों में हो रहे परिवर्तन के कारण कीमतें अस्थिर हो गई हैं, जिससे समग्र रूप में उभरते बाजारों में वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट आई है।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 3, Issue 12, December 2020 |

भुगतान संतुलन पर प्रभावः वैश्विक लॉकडाउन के कारण आयात- निर्यात आर्डर में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी आयी है। कच्चे तेल की कीमतों में कमी, स्वर्ण एवं अन्य आयातों में गिरावट से व्यापार घाटे में कमी हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार स्वर्ण की कीमतों में वृद्धि के कारण मार्च के अंतिम सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है।

मुद्रास्फीतिः RBI के अनुसार निम्न प्रतिफल और कम आय के कारण मांग में गिरावट एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तनावग्रस्त स्थिति में मुद्रास्फीति गिरकर 2.4 प्रतिशत हो गई।

करों पर प्रभावः कोविड-19 के कारण लाभ और आय में पहले की अपेक्षा कमी आयी है, जिससे प्रत्यक्ष करों में वृद्धि नहीं की जा सकती है और न ही अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि की जा सकती है। क्योंकि अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि होने से यह स्फीतिकारी सिद्ध होगा और गरीब लोगों को अत्यधिक प्रभावित करेगा साथ ही साथ मांग में और अधिक कमी आएगी।

निवेशः निवेश से संबंधित सबसे प्रचलित मॉडल हैराड-डोमर मॉडल है, जो बताता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में बचत जितना ज्यादा अधिक होगा, निवेश भी उतना ही अधिक होगा। परंतु कोविड-19 के कारण देश भर में हुए लॉकडाउन के प्रभाव से देश में बेरोजगारी की दर में बढोतरी हुई है, जिससे बचत में कमी आई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार निवेश की संभावनाओं में कमी बनी हुई है।[11,12]

समाधान

आरबीआई गवर्नर के अनुसार कोविड-19 जैसी महामारी से उत्पन्न कठिन चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक अपने सभी साधनों या युक्तियों का उपयोग करेगा। उन्होंने कहा कि व्यापक उद्देश्य यह सुनिश्चित करने में मदद करना है कि सभी हितधारकों, विशेषकर वंचितों और कमजोर तबकों के लोगों तक वित्त का प्रवाह निरंतर बना रहे।

तरलता प्रबंधन

लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालनः 50,000 करोड़ रुपये की कुल प्रारंभिक राशि के साथ 'लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ 2-0)' का दूसरा सेट कार्यान्वित किया जाएगा। यह कदम एनबीएफसी और एमएफआई सहित छोटे एवं मध्यम आकार की उन कंपनियों तक धन प्रवाह को सुगम बनाने के लिए उठाया जा रहा है, जो कोविड-19 के कारण आए व्यवधानों से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं: 50,000 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को प्रदान की जाएंगी, ताकि उन्हें विभिन्न सेक्टरों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों एवं माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए नाबार्ड को 25,000 करोड रुपये उधार देने/पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी को 15,000 करोड़ रुपये और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए, एनएचबी को 10,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। तथा ये सुविधाएं इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये संख्या कोविड-19 से उत्पन्न कठिन वित्तीय परिस्थितियों के मद्देनजर बाजार से वित्त जुटाने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।[13,14]

रिवर्स रेपो रेट में कमीः रिवर्स रेपो रेट को तत्काल प्रभाव से 0.25 प्रतिशत कम करके 3.75 प्रतिशत कर दिया गया है, ताकि बैंकों को अपने अधिशेष धन को निवेश करने और अर्थव्यवस्था के उत्पादक सेक्टेरों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अर्थापाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा में वृद्धिः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अर्थापाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा में 60 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इसका उद्देश्य कोविड-19 को नियंत्रण में रखने एवं इसमें कमी लाने के प्रयासों के लिए राज्यों को अधिक से अधिक सहूलियत प्रदान करना और उनके बाजार उधारी कार्यक्रमों की योजना बेहतर ढंग से बनाने में उनकी मदद करना है। यह व्यवस्था आरबीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली अस्थायी ऋण सुविधाएं हैं, जो सरकारों की प्राप्तियों और व्यय में अस्थायी असंतुलन को कम करने में उनकी मदद करती हैं।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 3, Issue 12, December 2020 |

निष्कर्ष

नियामकीय उपाय

परिसंपत्ति वर्गीकरणः किसी परिसंपत्ति को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) मानने के संबंध में केंद्रीय बैंक ने निर्णय लिया है कि परिसंपत्तियों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करते समय उस भुगतान स्थगन अवधि पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसे मंजूर करने की अनुमति उधार देने वाले संस्थानों को आरबीआई घोषणा के अनुसार दी गई है। इसका मतलब यही है कि उन खातों के लिए 90-दिवसीय एनपीए मानदंड पर विचार करते समय भुगतान स्थगन अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, जिनके लिए उधार देने वाले संस्थानों ने स्थगन या मोहलत देने का निर्णय लिया है .

समाधान योजना के कार्यान्वयन की अवधी में वृद्धिः भुगतान न की जा रही उन परिसंपत्तियों या खातों से जुड़े विवादों के समाधान की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समाधान योजना के कार्यान्वयन की अवधि 90 दिन बढ़ा दी गई है, जो या तो अभी एनपीए है या जिनके एनपीए बन जाने की आशंका है।[15,16]

लाभांश का वितरणः अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक संबंधित मुनाफे से आगे कोई लाभांश भुगतान नहीं करेंगे। इसकी निर्णय की समीक्षा दूसरी तिमाही के अंत में बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर की जाएगी। ऐसा बैंकों को पूंजी संरक्षण में सक्षम बनाने के लिए किया गया है, ताकि वे बढ़ती अनिश्चितता के माहौल में अर्थव्यवस्था को आवश्यक सहयोग देने और नुकसान को झेलने की अपनी क्षमता को बरकरार रख सकें।

तरलता कवरेज अनुपात में कमीः विभिन्न संस्थानों के लिए तरलता की स्थिति बेहतर करने के उद्देश्य से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए तरलता कवरेज अनुपात की आवश्यकता को तत्काल प्रभाव से 100 प्रतिशत से कम करके 80 प्रतिशत के स्तर पर ला दिया गया है।

आपात ऋण सहायता गारंटी योजनाः केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की संचालन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें तीन लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए आपात ऋण सहायता गारंटी योजना की शुरुआत की। इस योजना से लॉकडाउन के बाद 19 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को अपना कारोबार फिर से शुरु करने में मदद मिलेगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाः इसके तहत 1-7 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की गई। इससे तरलता को बढावा मिलेगा तथा मांग को बढावा मिलने के साथ-साथ औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों क्षेत्रकों की चुनौतियों को कम किया जाएगा।

सुझाव

- IMF के अनुसार सीमित घरेलु संसाधनों वाले उभरते बाजारों को इस संकट से निपटने के लिए 2.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्कता होगी।
- व्यक्तिगत व्यय या उपभोग व्यय अर्थव्यवस्था में संवृद्धि को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत घोषित की गई राहत पैकेज की राशि को बढाने की आवश्यकता है।
- लॉकडाउन के प्रभाव के कारण अनौपचारिक क्षेत्रें में कार्यरत श्रमिकों का अपने गांव की ओर पलायन ग्रामीण आजीविका को प्रभावित कर सकता है। इसके समाधान के लिए ग्रामीण अवसंरचना में सुधार करने और विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योगों को बढावा दिया जा सकता है।[17]

संदर्भ

1. "लॉकडाउन में राहत के बाद भी ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रही अर्थव्यवस्था? जानें". जनसत्ता. 2019
2. ↑ "कोरोना के सामने घुटनों पर आई दुनिया की अर्थव्यवस्था". आज तक. 2019
3. ↑ "आईएमएफ ने कहा, कोविड-19 का लगातार फैलाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा". हिन्दुस्तान लाइव. 2019
4. ↑ "कोरोना वायरस के कारण भारत में पैदा हुईं आर्थिक चुनौतियां". ORF. 2020
5. ↑ Ward, Alex (2020). "India's coronavirus lockdown and its looming crisis, explained". Vox (अंग्रेज़ी में).

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 3, Issue 12, December 2020 |

6. ↑ Bureau, Our. "PM Modi calls for 'Janata curfew' on March 22 from 7 AM-9 PM". 2019
7. ↑ "India's 1.3bn population told to stay at home". BBC News (अंग्रेज़ी में). 2019
8. ↑ "पूरा देश लॉकडाउन की ओर, 31 मार्च से पहले फिर हो सकता है जनता कर्फ्यू का आह्वान". अमर उजाला. 2020
9. ↑ "कोरोना का प्रभाव, 2020 में 4.5 फीसदी GDP का अनुमान: सरकार". अमर उजाला. 2020
10. ↑ "Coronavirus Update (Live): 25,592,318 Cases and 853,437 Deaths from COVID-19 Virus Pandemic - Worldometer". www.worldometers.info (अंग्रेज़ी में).2019
11. ↑ अहमद, ज़ुबैर (2020). "कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था स्वदेशी की तरफ़ जाएगी?". BBC News
12. ↑ शर्मा, अभय. "कैसे इस बुरे वक्त में हमारे गांव देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा रहे हैं". सत्याग्रह. 2019
13. ↑ "कोविड-19: भारत में 'लॉकडाउन' से प्रवासी कामगारों पर भारी मार". संयुक्त राष्ट्र समाचार. 2019
14. ↑ राय, निधि (2020). "कोरोना वायरस से भारत की आर्थिक परेशानियाँ कितनी बढ़ीं?". बीबीसी हिन्दी.
15. ↑ "क्या सरकार जल्द ही करने वाली है एक और आर्थिक पैकेज का ऐलान?". ज़ी न्यूज़. 2020
16. ↑ "At -23.9%, GDP Contracts For First Time In Over Four Decades". NDTV.com.2019
17. ↑ "6 फैक्टर जिससे पता चलता है कि देश की इकॉनमी में सुधार की शुरुआत हो चुकी है". नवभारत टाइम्स. 2020